2008 में 31 दिसंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) अस्तित्व में आई। यह देश में आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करती हैं, जो राज्य सरकारों की विशेष इजाजत के बगैर केंद्र के अधीन काम करती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्यों के अधिकार का हनन का हवाला देकर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

अमेरिका की तरह निपटना होगा आतंकवाद से

खरी बात ▶ सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को फिर दी परोक्ष चेतावनी

कहा, कोई देश आतंक से बाज नहीं आता तो कठोर कार्रवाई ही विकल्प

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आतंकवाद का पालन-पोषण बंद नहीं करने पर पाकिस्तान को और सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जब तक आतंक का जड़ से सफाया नहीं हो जाता तब तक भारत की लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने आतंकवाद पर अमेरिका की तर्ज पर भारत के भी सख्त कार्रवाई करने के इरादे जाहिर किए। पाकिस्तान को परोक्ष चेतावनी देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि आतंकी फंडिंग के लिए ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी कोई देश आतंक की हिमाकत से बाज नहीं आता तो फिर कठोर कार्रवाई ही विकल्प रह जाएगा।

सुरक्षा और कूटनीति से जुड़े रायसीना डायलॉग को संबोधित करते हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा जबतक राष्ट्रों के स्तर पर इसका पालन-पोषण करने से लेकर धन और हथियार उपलब्ध कराया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि इसीलिए अगर आतंक का अंत करना है, तो फिर 9/11 के बाद अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ जैसी कार्रवाई शुरू की उसी तरह के सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आतंक की जड़ को समझते हुए हमें इसकी बुनियाद पर प्रहार करना होगा। नाम लिए बिना आतंक पर पाक के दोहरे चरित्र को बेनकाब करते हुए रावत ने कहा कि जो देश आतंक का समर्थन करते हैं, वे इसके खिलाफ वैश्विक लड़ाई का हिस्सा नहीं हो सकते। रावत ने कहा कि आतंक को पनाह देने वाले देशों को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग कर उन्हें सबक सिखाना ही होगा।

रायसीना डायलॉग में गुफ्तगू : भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरल बिपिन रावत गुरुवार को नई दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग-2020 में अफगानिस्तान-पाकिस्तान के लिए ब्रिटेन के विशेष प्रतिनिधि गैरेथ बेली के साथ गुफ्तगू करते नजर आए। गैरेथ बेली ब्रिटेन की विदेश और कॉमनवेल्थ ऑफिस में दक्षिण एशियाई मामलों के निदेशक भी हैं। प्रेट्र

आतंकी फंडिंग के लिए एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में पाकिस्तान को डाले जाने की जरूरत बताते सीडीएस ने कहा कि जो भी देश आतंक का समर्थन करता है, उसे सबक सिखाना होगा। इस लिहाज से एफएटीएफ की ओर से ब्लैकलिस्ट किया जाना अच्छा कदम है। फिर भी कोई देश इससे बाज नहीं आता तो और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत होगी।

रावत ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच चल रही शांति वार्ता का समर्थन किया, मगर यह भी कहा कि सौदेबाजी दीर्घकालिक समाधान के लिए होनी चाहिए। यह अस्थायी नहीं होनी चाहिए। तालिबान हो चाहे कोई भी आतंकी संगठन, उसे पहले हथियार डालना होगा, तभी मुख्यधारा की राजनीतिक प्रकिया में शासन का विकल्प उसको मिलेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में कट्टरपंथ की चुनौतियों की चर्चा करते हुए रावत ने कहा कि कश्मीर में हमने देखा है कि कट्टरपंथ का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि हम आज देख रहे कि छोटे-छोटे बच्चों के दिमाग में कट्टरपंथ का जहर भरा जा रहा है। इसीलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए और उन्हें हम कट्टरपंथ से मुक्त करने वाले कैंपों (डि-रेडिक्लाइज कैंप) में भेजें।

सीडीएस बिपिन रावत ने कट्टरपंथी विचाराधारा की चुनौती को थामने के लिए ऑनलाइन कट्टरपंथ पर भी लगाम की बात कही। वहीं, कश्मीर में पैलेट गन से बड़ी तादाद में लोगों के घायल होने की घटनाओं से जुडे सवाल पर उन्होंने कहा कि सेना पर अतिरेक कार्रवाई का आरोप लगाना सही नहीं है। हम आक्रामक होते तो फिर हमारे सैनिक इतनी ज्यादा संख्या में नहीं मारे जाते। साथ ही यह भी कहा कि अब पत्थरबाजी सरीखी घटनाओं से निपटने के लिए हमने नई रणनीति बनाई है और पैलेट गन का विशेष परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाता है।

ओआइसी के लिए जरूरी होगा ईरान का साथ

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

अपने रणनीतिक साझेदार और मित्र देश अमेरिका के गुस्से की चिंता किए बगैर अगर भारत ईरान के साथ हमदर्दी दिखाने में जुटा है तो इसके पीछे भी कश्मीर मुद्दा है। पाकिस्तान ने हाल में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से बात की है कि इस्लामिक देशों के संगठन ओआइसी में कश्मीर पर विशेष बैठक बुलाई जाए। अगर ऐसा होता है तो भारत को ईरान की मदद चाहिए जो ओआइसी का बड़ा सदस्य है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ भारत के तीन दिनों के दौरे पर आए हुए हैं।

ईरान पर अभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हैं, इसलिए ईरान के लिए ज्यादा जरूरी अभी कारोबार है। नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री की रूस, यूरोपीय संघ समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से बात हुई है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ के साथ हालिया क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने ईरान व वैश्विक शक्तियों के बीच 2015 में हुए परमाणु समझौते पर भी चर्चा की।

आस्ट्रेलिया, डेनमार्क व हंगरी के विदेश मंत्रियों से मुलाकात : जयशंकर ने गुरुवार को आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिसे पायने, हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिज्जार्तो और डेनमार्क के विदेश मंत्री जिप्पे कोफोड से मुलाकात और उनके साथ द्विपक्षीय महत्व के मसलों पर चर्चा की।

'हिंद-प्रशांत का मकसद किसी को अलग-थलग करना नहीं'

नई दिल्ली, प्रेट्र : हिंद-प्रशांत का उद्देश्य क्षेत्र में चीन के दबदबे को रोकने वाला बताने पर अमेरिका व भारत ने गुरुवार को रूस पर निशाना साधा। दोनों ने कहा कि इसका मकसद किसी देश को अलग-थलग करना नहीं बल्कि यह 'सिद्धांत आधारित सोच' है। रायसीना डायलॉग में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि इसका मकसद मौजूदा क्षेत्रीय ढांचों को नुकसान पहुंचाना है। अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मैथ्यू पॉटिंगर ने कहा कि यह उन देशों का समुदाय है जो कानून के शासन का सम्मान करता है, समुद्री क्षेत्र व आसमान में परिवहन की आजादी का समर्थन करता है। भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा, 'सदियों से भारत का चीन व दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क रहा है। यह औपनिवेशिक काल में टूट गया...वैश्विक साझा क्षेत्र बेहद अहम हैं व हिंद प्रशांत एक वैश्विक साझा क्षेत्र है।'

न्यूज गैलरी

सीमा शुल्क उपायुक्त की 3.56 करोड़ की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीमा शुल्क विभाग के उपायुक्त रैंक के एक अधिकारी की 3.56 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी के मुताबिक यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई है। जांच एजेंसी की ओर से जारी बयान में कहा कि जब्त संपत्ति में बैंकों में जमा 47.58 लाख रुपये, म्यूचुअल फंड में 91.75 लाख रुपये, 74 लाख रुपये की बीमा पालिसी, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में 52.43 लाख रुपये मूल्य की जमीन, पटना में 35 लाख रुपये कीमत का एक फ्लैट, 40.33 लाख रुपये के आभूषण और अधिकारी से जब्त किए गए 14.50 लाख रुपये नकद शामिल हैं। जांच एजेंसी के अनुसार अधिकारी का शुरुआती नाम शशिकांत है। ईडी ने अधिकारी और उनके परिवार के नाम की संपत्ति जब्त करने के लिए प्रोविजनल आदेश जारी किया था और संपत्ति का कुल मूल्य 3.56 करोड़ रुपये है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति एकत्र करने के मामले में अधिकारी की जांच की जा रही है। ईडी ने कहा कि उसने सीवीसी की टिप्पणी और अधिकारी के खिलाफ दर्ज सीबीआइ की प्राथमिकी के आधार पर मनी लांड्रिंग कानून के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। (प्रेट्र)

एस्क्रो खाते से सुरक्षित होगा यमुना एक्सप्रेस वे का सफर

ग्रेटर नोएडा : यमुना एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा उपायों को लागू कराने के लिए एस्क्रो खाता खोला गया है। खाता खुलवाने के लिए यमुना प्राधिकरण ने जेपी इंफ्राटेक को आदेश दिए थे। एक्सप्रेस वे पर प्रतिदिन वसूल किए जाने वाले टोल से कुछ धनराशि इस खाते में जमा की जाएगी। यह धनराशि सुरक्षा उपायों को लागू करने में खर्च होगी। यमुना एक्सप्रेस-वे पर वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आइआइटी दिल्ली से सुरक्षा ऑडिट कराया गया था। आइआइटी ने एक्सप्रेस वे के लिए कई सुझाव दिए थे ताकि हादसों को रोका जा सके। इसके तहत मेडियन (दोनों मार्ग के बीच की जगह) के दोनों ओर क्रैश बीम बैरियर लगाना, एक्सप्रेस-वे पर दोनों किनारों पर लगे क्रैश बीम बैरियर की ऊंचाई बढ़ाना, रंबल स्ट्रिप, स्पीड गन, कैमरों की संख्या बढ़ाना आदि शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा से आगरा तक एक्सप्रेस-वे पर रोशनी के लिए एलईडी लगाने के निर्देश दिए थे। इन सुरक्षा उपायों में कुछ को जेपी इंफ्राटेक ने लागू किया। लेकिन अहम उपायों को धनराशि की कमी के कारण लागू नहीं किया गया। (जासं)

परीक्षा पे चर्चा : पीएम से इस बार 60 से ज्यादा बच्चे पूछेंगे सवाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- विदेशों में रहने वाले भारतीय बच्चे के भी हो सकते हैं सवाल
- कार्यक्रम में 50 दिव्यांग बच्चे भी खासतौर पर होंगे शामिल

छात्रों के साथ होने वाली 'परीक्षा पे चर्चा' में पिछले सालों के मुकाबले इस बार ज्यादा बच्चों को पीएम से सीधे सवाल पूछने का मौका मिलेगा। फिलहाल अब तक इस चर्चा में पीएम से करीब 15 छात्रों के सवाल ही होते थे, लेकिन इस बार करीब 60 छात्रों को पीएम से सवाल करने का मौका दिया जाएगा। हालांकि इनमें से प्रत्येक तीन से चार छात्रों के सवाल आपस में मिलते-जुलते या एक जैसे विषयों पर आधारित होंगे। पीएम से साथ परीक्षा पे चर्चा का यह कार्यक्रम फिलहाल 20 जनवरी को प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बराबर की संख्या में बच्चों का चयन किया गया है। साथ ही इनमें छात्र और छात्राओं की प्रतिशत भी करीब बराबर का ही रखा गया है। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम का देश भर के करीब 15 लाख शैक्षणिक संस्थानों और स्कूलों से सीधे प्रसारण की भी योजना बनाई गई है। यानि जो बच्चे कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाएंगे, वह स्कूल में ही बैठकर इसे देख सकेंगे।

पीएम 2018 से छात्रों के साथ इस तरह की चर्चा करते आ रहे है। इस बार कार्यक्रम में दो हजार बच्चे शामिल होंगे जिसमें करीब 50 दिव्यांग बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है। इन बच्चों का भी चयन देश भर से किया गया है।

20 देशों में रहने वाले भारतीय बच्चों ने भी पूछे है सवाल

प्रधानमंत्री की छात्रों के साथ होने वाली 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम को लेकर उत्साह सिर्फ भारतीय छात्रों में ही नहीं है, बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय बच्चों में भी है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए करीब 20 देशों में रहकर पढ़ाई कर भारतीय बच्चों ने भी सवाल भेजे है। फिलहाल जिन देशों से भारतीय बच्चों के सवाल आए है, उनमें रूस, ईरान, नेपाल, बहरीन, यूएई, सिंगापुर, कतर और जापान जैसे देश शामिल है।

फेमा मामले में ईडी के सामने पेश हुए कांग्रेस नेता केजे जार्ज

बेंगलुरु, प्रेट्र : फेमा मामले से जुड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केजे जार्ज गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के सामने पेश हुए। पूर्व मंत्री से ईडी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन के बारे में पूछताछ कर रही है।

ईडी के सामने पेश होने के बाद जार्ज ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों के सवालों का उत्तर दिया है और आगे सहयोग करते रहेंगे। कोई ब्योरा दिए बगैर उन्होंने कहा, 'ईडी ने मुझे समन किया था। कानून से बंधे नागरिक होने के नाते मैंने उत्तर दिए और जो दस्तावेज उन्होंने मांगे वह उनके हवाले किया। आगे भी वे मुझे बुलाते हैं तो मैं सहयोग करूंगा और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दूंगा।' जार्ज ने कहा कि ईडी ने उनके परिवार के सदस्यों को समन जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा, 'यदि जरूरत पड़ी तो वे (ईडी) मुझे फिर से बुला सकते हैं और मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं।'

पिछले वर्ष कर्नाटक राष्ट्र समिति के अध्यक्ष रवि कृष्ण रेड्डी ने ईडी को शिकायत सौंप कर जार्ज और उनके परिवार के सदस्यों की अमेरिका में संपत्ति और मनी लांड्रिंग की जांच करने की मांग की थी।

ब्रू जनजाति के लोग अब त्रिपुरा के होंगे निवासी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पूर्वोत्तर भारत की ब्रू जनजातियों की दो दशक पुरानी समस्या का समाधान निकल आया है। मिजोरम से भागकर आए और त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रह रहे 30 हजार से अधिक ब्रू जनजातियों को अब वापस जाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। केंद्र, त्रिपुरा, मिजोरम और ब्रू जनजातियों के प्रतिनिधियों के बीच समझौते के बाद अब उन्हें त्रिपुरा में ही बसाया जाएगा। इसके लिए गृहमंत्री अमित शाह ने 600 करोड़ रुपये के पैकेज का एलान किया है।

अमित शाह ने कहा कि ब्रू जनजातियों को त्रिपुरा में घर के लिए जमीन दी जाएगी। पांच हजार से अधिक परिवारों में से प्रत्येक परिवार के खाते में चार लाख रुपये का फिक्स्ड डिपोजिट किया जाएगा, जिसे वे दो साल बाद निकाल सकेंगे। उन्हें दो साल के लिए हर महीने पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा, उन्हें प्रति व्यक्ति के हिसाब से दो साल तक खाने के लिए मुफ्त राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। त्रिपुरा सरकार की ओर से दी गई जमीन का मालिकाना हक मिलने के बाद उन्हें डेढ़ लाख रुपये मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि वे अब त्रिपुरा के निवासी माने जाएंगे।

त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रह रहे ब्रू जनजातियों के मुद्दे पर गुरुवार को नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (मध्य में), त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव (दाएं) और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा (बाएं)। प्रेट्र

मिजोरम में 30 हजार से अधिक ब्रू शरणार्थी

मिजोरम के 30 हजार से ज्यादा ब्रू जनजाति के लोगों को शरणार्थी का जीवन बिताना पड़ रहा है। 1997 में मिजो जनजाति से संघर्ष के बाद ब्रू जनजाति के ये लोग स्थायी रूप से त्रिपुरा में रह रहे हैं।

कौन हैं ब्रू जनजाति : ब्रू या रिआंग जनजाति के लोग पूर्वोत्तर के राज्यों में बसते हैं। खासतौर से ये मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी असम में बसे हैं। यह मिजोरम के ममित और कोलासिब जिलों में बसे थे।

ऐसे शुरू हुआ संघर्ष

1995 में मिजो और ब्रू के बीच संघर्ष के बाद युवा मिजो एसोसिएशन और मिजो स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ब्रू जनजाति को राज्य में मताधिकार से वंचित किए जाने की मांग की। विवाद था कि ये मिजोरम के स्थायी निवासी नहीं हैं। इसके बाद उग्रवादी संगठन बीएनएलएफ और बीएनयू अस्तित्व में आए। 21 अक्टूबर 1997 में बीएनएलएफ उग्रवादियों ने मिजोरम में एक वन अधिकारी को मार गिराया। इसके जवाब में जातीय हिंसा शुरू हो गई। बीएनयू ने स्वायत्तशासी आदिवासी जिले बनाने की मांग की।

रक्षा मंत्री ने देश को समर्पित किया स्वदेशी के-9 वज्र टैंक

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सूरत के हजीरा में लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) के आर्मर्ड सिस्टम्स कांप्लेक्स में निर्मित के-9 वज्र टैंक देश को समर्पित किया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत यह पूरी तरह देश में निर्मित तोप है।

टैंक की फ्लैगशिप सेरेमनी में राजनाथ सिंह ने बताया कि लार्सन एंड टुब्रो को भारतीय सेना ने सौ के-9 वज्र टैंक बनाने का ऑर्डर दिया है। अब तक 51 टैंक तैयार किए जा चुके हैं। यह टैंक जैविक हमले से सुरक्षित है और 15 सेकेंड में एक साथ तीन गोले छोड़ने में सक्षम है। 100 हॉर्सपावर का इंजन इस टैंक को ताकतवर बनाता है। ऑटोमैटिक लोडेड क्षमता से लैस यह टैंक 40 किमी तक दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना आज पहले से काफी मजबूत और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित हुई है। इसी कड़ी में देश में पहली बार डिफेंस इंवेस्टमेंट सेल का गठन होगा जो देश के आर्मर्ड सिस्टम को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ इसके आधुनिकीकरण और निवेश को देखेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले देश में यह बात सोची ही नहीं गई कि सैन्य क्षेत्र में निजी भागीदारी हो सकती है। इसका सबसे अधिक लाभ सेना को ही होगा। लार्सन एंड टुब्रो रक्षा क्षेत्र का रणनीतिक साझीदार है जो टैंक बना रहा है, अब आर्मर्ड व्हीकल भी बनाए जाएंगे।

राजनाथ ने कहा कि देश की सेना की जरूरत के 500 कंपोनेंट अभी विदेश से आयात किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इनमें से अधिकतर का मेक इन इंडिया के तहत देश में ही निर्माण संभव होगा। वर्ष 2025 तक देश के सैन्य साजो-सामान का टर्नओवर एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये या करीब 26 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस क्षेत्र में 23 मिलियन युवाओं को रोजगार देने की क्षमता है। समारोह में लार्सन एंड टुब्रो के ग्रुप चेयरमैन एम. नायक भी मौजूद थे।

गुजरात के सूरत में गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित के-9 वज्र टैंक को विधिपूर्वक पूजा-अर्चना के साथ देश को समर्पित किया। इस दौरान टैंक पर स्वास्तिक बनाते राजनाथ सिंह। प्रेट्र

भारतीय तटरक्षकों को 50 जहाज और 16 एडवांस हल्के हेलीकॉप्टर मिलेंगे

चेन्नई, प्रेट्र : भारतीय तटरक्षकों के बेड़े में 50 नये जहाज और 16 एडवांस हल्के हेलीकॉप्टर और जुड़ जाएंगे। इसके साथ ही भारतीय तटरक्षकों के पास वर्ष 2025 तक कुल 200 जहाज और 100 विमान होंगे। तटरक्षक महानिदेशक कृष्णस्वामी नटराजन ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका के बाद जापान के पास दुनिया का दूसरे सबसे बड़े तटरक्षक सुरक्षा बल हैं। 145 जहाजों और 62 विमानों के साथ भारतीय तटरक्षकों को दुनिया का चौथा सर्वश्रेष्ठ तटरक्षक होने का दर्जा हासिल हुआ है। उन्होंने बताया कि इस समय विभिन्न भारतीय शिपयार्ड में 50 जहाज निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, बेंगलुरु स्थित एचएएल में 16 एमके3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों का उत्पादन हो रहा है। चेन्नई के तट से 50 नॉटिकल मील दूर भारत-जापान के 19वें संयुक्त अभियान के बाद नटराजन ने बताया कि मार्च 2020 तक ट्विन इंजन वाला पहला हेलीकॉप्टर दस्ते में शामिल होने की उम्मीद है।

नई शिक्षा नीति के लिए मिल सकता है खास पैकेज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ प्रस्तावित नीति की ज्यादातर सिफारिशों को पांच साल में ही अमल करने का है प्रस्ताव

बजट में इस बार शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देने वाली कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। वैसे भी नई शिक्षा नीति के माध्यम से इसे मजबूती देने का पूरा मसौदा तैयार है। अभी इसकी अधिकारिक घोषणा शेष है, लेकिन इसके अमल को लेकर सरकार को एक बड़ी पूंजी की जरूरत होगी। ऐसे में सरकार इसके लिए एक पैकेज की घोषणा कर सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी इसे लेकर वित्त मंत्रालय को अपनी राय दी है।

वैसे भी पिछले वर्षों में सरकार का जोर शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर दिखा था। ऐसे में माना जा रहा है कि अब शिक्षा को लेकर जो भी प्रावधान होगा, वह नई शिक्षा नीति को केंद्रित करते हुए ही होगा। स्कूली शिक्षा की तर्ज पर इस बार उच्च शिक्षा के बिखरे ढांचे को भी समेटने की कोशिश हो सकती है। इसमें विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, प्रबंधन संस्थान और टीचर एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में बंटी पूरी उच्च शिक्षा को एक दायरे में लाया जा सकता है। दो साल पहले प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक जैसे स्कूली शिक्षा को एक साथ जोड़कर समग्र शिक्षा के दायरे में लाया गया था।

सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के अमल का फिलहाल जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसके तहत अगले पांच वर्षों में उसे पूरी तरह से लागू करने की सिफारिश की गई है। ऐसे में इस बदलाव के लिए सरकार को भारी भरकम बजट की भी जरूरत होगी। मौजूदा समय में शिक्षा का जो बजट है, उनमें प्रस्तावित नई शिक्षा नीति की सिफारिशों को लागू करना संभव नहीं है। मौजूदा समय में देश में शिक्षा का कुल बजट करीब 94 हजार करोड़ रुपये है। इनमें स्कूली शिक्षा के लिए करीब 56 हजार करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा के लिए करीब 38 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

हाई-फाई ट्रेन

रेल मंत्री पीयूष गोयल हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना, आइआरसीटीसी की दूसरी लग्जरी ट्रेन की अहमदाबाद से होगी शुरुआत, मुख्यमंत्री रूपाणी रहेंगे मौजूद

अहमदाबाद-मुंबई तेजस को आज हरी झंडी

नई दिल्ली, प्रेट्र : रेल मंत्री पीयूष गोयल व गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी शुक्रवार को अहमदाबाद-मुंबई तेजस एक्सप्रेस को अहमदाबाद से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह दूसरी ऐसी ट्रेन है, जिसका संचालन रेलवे की खानपान व पर्यटन इकाई आइआरसीटीसी करेगी। इस प्रकार की पहली ट्रेन पिछले साल लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाई जा चुकी है।

रेलवे ने बताया कि इस ट्रेन का परिचालन 19 जनवरी को अहमदाबाद से किया जाएगा। टिकट की बुकिंग ऑनलाइन होगी। आइआरसीटीसी की वेबसाइट और उसके ऑनलाइन साझीदार पेटीएम, फोनपे, मेक माई ट्रिप, गूगल, आइबीबो, रेल यात्री आदि एप के माध्यम से टिकट बुक किए जा सकते हैं। ट्रेन संख्या 82902/82901 अहमदाबाद-मुंबई-अहमदाबाद का संचालन हफ्ते में छह दिन किया जाएगा। गुरुवार को ट्रेन का मेंटेनेंस कार्य होगा। पूरी तरह वातानुकूलित तेजस में एक्जक्यूटिव क्लास चेयर कार की दो बोगियां होंगी, जिनमें 56-56 सीटें होंगी। इसके अलावा चेयर कार की आठ बोगियां होंगी और प्रत्येक में 78 साटों का प्रावधान होगा। इस ट्रेन की कुल क्षमता 736 यात्रियों की है। अहमदाबाद से यह सुबह 6:40 बजे चलेगी और दोपहर 1:10 बजे मुंबई पहुंचेगी। इस बीच यह नांदेड़, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी और बोरीवली में रुकेगी। वापसी में मुंबई से अपराह्न 3:40 बजे चलेगी और अहमदाबाद में रात 9:55 बजे पहुंचेगी।

पीयूष गोयल फाइल फोटो

इसके टिकट में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं मिलेगी। पांच साल से ज्याद उम्र के बच्चों का भी पूरा टिकट लगेगा और उन्हें सीट आवंटित की जाएगी। बुकिंग के दौरान पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का उल्लेख करना होगा। हालांकि, इनका न तो किराया लगेगा, न ही सीट आवंटित होगी। तेजस में डायनेमिक फेयर का प्रावधान होगा। यानी, व्यस्त और कम व्यस्त तथा मांग के अनुरूप किराये में बदलाव होगा। इसमें तत्काल कोटा नहीं होगा।

यात्रियों को 25 लाख का मुफ्त बीमा : आइआरसीटीसी तेजस में यात्रा करने वाले सभी लोगों को 25 लाख का यात्रा बीमा मुफ्त में देगी। इसमें यात्रा के दौरान यात्रियों के सामान की चोरी और डकैती जैसी वारदातों के लिए भी एक लाख के बीमा का प्रावधान शामिल है।

विदेशी पर्यटकों के लिए 18 सीटें रहेंगी आरक्षित : इस ट्रेन में विदेशी पर्यटकों के लिए कुल 18 सीटें आरक्षित रहेंगी। इनमें ईसी की छह और सीसी की 12 सीटें शामिल हैं।

ट्रेन देर हुई तो आइआरसीटीसी यात्रियों को देगी मुआवजा : अन्य खास सुविधाओं के साथ-साथ अहमदाबाद-मुंबई तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए आइआरसीटीसी ने पहली बार मुआवजे का प्रावधान किया है। इसके अनुसार, अगर ट्रेन एक घंटे से ज्यादा लेट होती है तो आइआरसीटीसी प्रत्येक यात्री को 100 रुपये का मुआवजा देगी, जबकि दो घंटे से ज्यादा लेट होने पर 250 रुपये का भुगतान करेगी।

मैच फिक्सर संजीव चावला 20 को लाया जाएगा भारत

जासं, नई दिल्ली : वर्ष 2000 में भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टेस्ट सीरीज में भारत की जीत सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैंसी क्रोनिए को मैच फिक्सिंग करने के एवज में 30 हजार डॉलर देने का ऑफर करने वाले मैच फिक्सर संजीव चावला को 20 जनवरी को लंदन से प्रत्यर्पण पर भारत लाया जाएगा। लंदन हाई कोर्ट ने चावला की अपील खारिज कर दी है। टेस्ट सीरीज के तीसरे दिन भारत की जीत सुनिश्चित करने के लिए चावला ने हैंसी क्रोनिए को मैच हारने को कहा था। दोनों की बात लीक होने पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा केस दर्ज करते ही चावला लंदन भाग गया था। भारतीय पासपोर्ट रद होने पर लंदन की नागरिकता ले ली। मुख्य आरोपित चावला के लंदन में होने के कारण क्राइम ब्रांच उक्त केस की तफ्तीश नहीं कर पा रही थी। 20 साल बाद इस केस की जांच अब आगे बढ़ेगी।

कह के रहेंगे
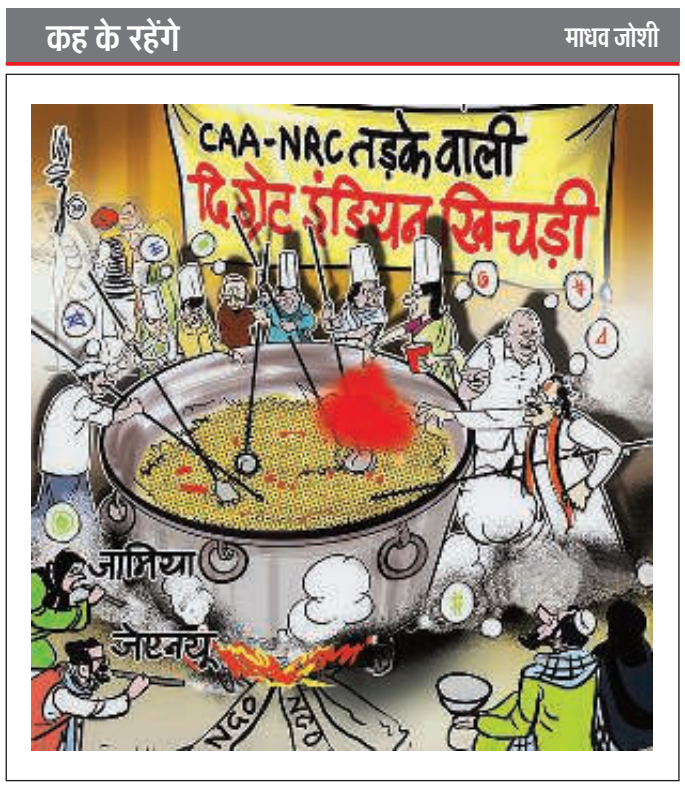
माधव जोशी